साप्ताहिक
Live not just breaTHE

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

दि कार्मिक पोस्ट

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 7, अंक : 41 (प्रति बुधवार), इन्दौर 1 जून 2022 से 7 जून 2022 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

योगी सरकार पर्यावरण संरक्षण पर भी दे रही जोर, उठाया जा रहा है बड़ा कदम

वाराणसी योगी सरकार इस साल वृक्षारोपण का महाअभियान चलाएगी। इसके लिए वन विभाग ने कमर कस लिया है। योगी सरकार ऐसे पौधों को लगाने पर जोर दे रही है। जो हवा को अधिक शुद्ध करे , फलदार हो और औषधीय गुण वाले हो । वाराणसी मंडल में इस बार 1 करोड़ 72 लाख पौधे लगाने की तैयारी है। अकेले वाराणसी में 20 लाख 77 हज़ार पौधे रोपित किए जाएंगे। सभी सरकारी विभाग इस महाअभियान में शामिल होंगे व पौधे लगाएंगे।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विकास के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रख रही है। वाराणसी की आबोहवा को सुधारने के लिए योगी सरकार ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। सरकार वृक्षारोपण का महाअभियान चलने जा रही है। इससे वायुमण्डल में ऑक्सीजन की शुद्ध मात्रा को बढ़ाने व वातावरण को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। वाराणसी सर्किल के मुख्य वन संरक्षक व प्रभारी वन संरक्षक प्रमोद गुप्ता ने बताया कि फ़लदार व ऑक्सीजन देने वाले पौधों को अधिक लगाने की योजना है। सहजन,पीपल,पाकड़ ,बरगद,अर्जुन,जामुन आवला ,अमरुद ,आम ,सागौन ,शीशम आदि के ज़्यादा पौधों के रोपण की तैयारी है। अकेले वाराणसी में क़रीब 20 लाख 77 हज़ार पौधे लगाने का लक्ष्य है । गाज़ीपुर में क़रीब 41 लाख 24 हज़ार,जौनपुर में लगभग 53 लाख 12 हज़ार ,चंदौली में करीब 57 लाख 32 हज़ार पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। गाज़ीपुर और जौनपुर में अमरुद के पौधों की ज़्यादा मांग है। सभी जिलों को मिलाकए वाराणसी मंडल में करीब 1 करोड़ 72 लाख पौधे लगाए जाने की महायोजना है।मानसून की शुरुआत के साथ ही वाराणसी में पौधारोपण का महाभियान शुरू होगा। वन विभाग के अलावा 26 अन्य विभाग वृक्षारोपण करने में भाग लेंगे। किस विभाग को कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है ,उसकी सूची भी वन विभाग ने बना लिया है। इस साल पौधा रोपण में कई प्रजातियों के पौधे लगाने की योजना है। पशुपालन विभाग चारे वाले पौधों की मांग करता है। बिजली विभाग काम ऊंचाई वाले पौधों को लगाना चाहता है। जनता की सहभागिता के लिए पौधे लगाने के इच्छुक जनता को भी पौधे देने की योजना बनाई जा रही है। जिससे अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो सके और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिले।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 5 जून को साइकिल रैली करेगी आयोजित

नई दिल्ली लोग अपनी दौड़ती-भागती जिन्दगी में पर्यावरण और इसके महत्त्व को अनदेखा कर देते हैं। प्रकृति जीवन का सबसे बड़ा आधार है। इसके संरक्षण के लिए हर किसी को आगे आकर इसके लिए काम करना होगा। क्योंकि हरा-भरा पर्यावरण ही हमारे जीवन और स्वास्थ्य पर सकारात्मक डालता है। हर साल 5 जून को पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका सामना हमारा ग्रह पृथ्वी कर रहा है। इस वर्ष पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि लोगों में फिटनेस, शारीरिक गतिविधियों और गैर-संचारी रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 5 जून को साइकिल रैली आयोजित की जाएगी।

विश्व पर्यावरण दिवस को मानव जीवन में स्वस्थ और हरित पर्यावरण के महत्व को बढ़ाने के लिए, 1974 से, सरकार, संगठनों द्वारा कुछ सकारात्मक पर्यावरणीय कार्यों को लागू करके पर्यावरण के मुद्दों को हल करने के लिए हर साल 5 जून को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि वर्ष 1972 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण राजनीति का विकास जो पर्यावरण के मुद्दों पर पहला बड़ा सम्मेलन है, संयुक्त राष्ट्र के तहत स्टॉकहोम में 5-16 जून से आयोजित किया गया था। इस सम्मलेन को मानव पर्यावरण सम्मेलन या स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता था। इसका उद्देश्य मानव पर्यावरण को संरक्षित करने और इसे बढ़ाने की चुनौती पर गौर करना था। फिर, उसी वर्ष 15 दिसंबर को, महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित करने का एक प्रस्ताव अपनाया गया। इसके अलावा, 15 दिसंबर को महासभा द्वारा एक और प्रस्ताव अपनाया गया जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) का निर्माण हुआ। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में केवल एक पृथ्वी% के नारे के साथ इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाया गया था।

अपना रंग बदलकर पर्यावरण प्रदूषण का संकेत देते हैं घोंघे

शिमला हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले घोंघे अपना रंग और व्यवहार बदलकर पर्यावरण में जहरीली गैसे घुलने का समय पर संकेत देते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का संकेत वे उस वक्त दे देते हैं, जिस समय जहरीली गैसें मनुष्य, पशुओं या अन्य जीवों के लिए कम घातक होती हैं। ये मिट्टी में कीटनाशकों या अन्य रसायनों के घुलने से होने वाले दुष्प्रभाव का भी समय पर संकेत देते हैं। यह बात साफ है कि जहां स्वस्थ घोंघे होंगे, वहां जीने योग्य वातावरण होगा।

केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के पर्यावरण विज्ञान विभाग के विशेषज्ञों के अध्ययन से यह बात सामने आई है। यह अध्ययन पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉ. दीपक पंत ने अपने शोध विद्यार्थी वरुण धीमान के साथ मिलकर किया है। इन विशेषज्ञों का दावा है कि स्नेल यानी घोंघे पर्यावरण में आए बदलाव के संकेतकों के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। ये घोंघे किसी भी विपरीत मौसम, जलवायु या वातावरण में परिवर्तन सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया से देते हैं। डॉ. पंत ने बताया कि अलग-अलग धातुओं के हवा में घुलने से हुए प्रदूषण सेइन पर सीधा असर होता है। जहरीली धातुओं की वातावरण में मौजूदगी पर इसकी पीठ के खोल का रंग बदल जाता है। इस खोल के साथ धातुओं की तीव्र प्रतिक्रिया होती है। कीटनाशकों के अवशेष और अन्य कारणों से होने वाले जैविक प्रदूषण पर ये अंडे देना बंद कर देते हैं और अपना स्वभाव बदल देते हैं। ये जमीन के पूरी तरह से खराब होने से पहले ही इसके संकेत दे देते हैं।

सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, जल-थल और पर्यावरण के लिए भी जहर है हर एक सिगरेट

नई दिल्ली। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू उत्पादों के सेवन से शरीर को कितना नुकसान होता है, किस-किस तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, ये बातें 7 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक सभी को बहुत अछी तरह से पता है। अब आप सोच रहे होंगे, यहां 70 की जगह 100 साल भी तो लिखा जा सकता था? जरूर लिखा जा सकता था, पर पिछले दो दशक के आंकड़े उठाकर देख लें तो साफ हो जाता है कि तंबाकू उत्पादों के बढ़े हुए सेवन ने कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ा दिया है, लिहाजा लोगों को आयु कम हो गई है, मोटे तौर पर औसत आयु 60-70 तक सिमट कर रह गई है। तंबाकू उत्पादों से होने वाले नुकसान के इस लेख की शुरुआत इसी विषय को केंद्र बनाकर करते हैं।

इस सचाई से भी बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि तंबाकू के सेवन से होने वाले गंभीर खतरों से हम सभी अवगत होते हैं, फिर भी यह लत, हमारी जान से सौदा करती आ रही है। सामान्यतौर पर तंबाकू निषेध दिवस जैसे खास दिन पर इसके शारीरिक दुष्प्रभाव और रोकथाम के उपायों को लेकर चर्चा करके मामले को फिर एक बरस के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तंबाकू उत्पादों के कारण शरीर को होने वाले नुकसान पर अक्सर बात होती रही है पर यह दीर्घकालिक रूप हमारे पर्यावरण को कितना गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है, क्या आपका इस ओर ध्यान गया? चलिए इस बार तंबाकू उत्पादों से पर्यावरण में कैसे जहर घुल रहा है, इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं।

तंबाकू उत्पादों का पर्यावरण पर असर

इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम पर्यावरण पर केंद्रित है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी है और तंबाकू निषेध दिवस 2022 का थीम पर्यावरण बचाएं है। कई शोध इस खतरे को लेकर अलर्ट करते रहे हैं कि तंबाकू, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए किसी जहर से कम नहीं है। तंबाकू उत्पादों के वेस्ट (गुटखे के रैपर, कागज, सिगरेट का शेष हिस्सा) पारिस्थितिक तंत्र के लिए चुनौती बढ़ा रहे हैं। हर साल तंबाकू के सेवन के कारण होने वाले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोगों से 8 मिलियन (80 लाख) से अधिक लोगों की मौत हो रही है। वहीं तंबाकू उद्योग का कचरा, तंबाकू उत्पादों को बनाने और पैकेजिंग में पर्यावरण का भयंकर नाश किया जा रहा है। मतलब तंबाकू उत्पाद आपको बीमार तो बना ही रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चुनौती खड़ी हो रही है। इस गुणा-गणित को समझने के लिए हमें देश के तंबाकू उद्योग के बारे में जानना होगा। आइए उस तरफ रुख करते हैं।

भारत का तंबाकू उद्योग

भारत विश्व में तंबाकू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साल 1995 में यहां कुल 450 मिलियन किलोग्राम (करीब साढ़े चार लाख टन) तंबाकू का उत्पादन होता था, साल दर साल इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 के बीच, भारत ने 838.80 मिलियन डॉलर कीमत के तंबाकू उत्पादों का निर्यात किया। इस उद्योग की वृद्धि और तंबाकू उत्पादों की बढ़ती मांग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फरवरी 2021 की तुलना में 2022 में 12.78त वृद्धि के साथ भारत ने 78 मिलियन डॉलर कीमत के तंबाकू उत्पादों का निर्यात किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तंबाकू उत्पादों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान और इसके व्यापार का क्या संबंध है? है न, असल खेल तो यही है। जितनी तेजी से बढ़ती मांग, उतना ही पर्यावरण को क्षति। कैसे? आइए यह भी समझते हैं।

तंबाकू उत्पादों से पर्यावरण को कैसे नुकसान?

तंबाकू उत्पादों को तैयार करने में उस पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी हालत पहले से ही खराब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आंकड़े बताते हैं- वैश्विक स्तर पर सिगरेट को तैयार करने के लिए 60 करोड़ से अधिक पेड़ काटे जाते हैं और 22 बिलियन (2200 करोड़) लीटर से अधिक मात्रा में पानी खर्च होता है। इसके अलावा केवल उत्पादों के निर्माण में ही 8.40 करोड़ टन की मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। पेड़ों की कटाई, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, तीनों पर्यावरण के लिए चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। अफसोस इस तरफ ध्यान किसी का नहीं है।

इन आंकड़ों के आधार कहा जा सकता है कि तम्बाकू उगाना, उत्पादों का निर्माण और उपयोग करना हमारे पानी, मिट्टी, समुद्र तटों और वायुमंडल में जहर घोल रहा है। इसके बाद- हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया वाले एटीट्यूड में जो सिगरेट का धुंआ पर्यावरण में जा रहा है, वह हमारे जीवन के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए फिक्र बढ़ाने वाला है।

एक अध्ययन से पता चलता है- 10 वर्षों तक प्रदूषण वाले इलाकों में रहने से फेफड़ों के जितना नुकसान होता है, उतना ही नुकसान 30 साल तक रोजाना सिगरेट पीने से होता है। अब आप खुद ही सोचिए, सिगरेट किस तरह से हमारी सेहत के लिए आगे कुंआ पीछे खाई वाली स्थिति बनाते जा रहा है? अब तक हमने तंबाकू उत्पादों के निर्माण और इसके उपयोग से होने वाले पर्यावरणीय और सेहत से संबंधित जोखिमों के बारे में जाना। खतरा यहीं तक सीमित नहीं है, इन उत्पादों का कचरा मृदा और जल को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। भारत के लैंडफिल में हर साल 100 अरब से अधिक सिगरेट बट्स कचरे के रूप में इकट्ठा हो रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सिगरेट का फिल्टर सेल्युलोज एसीटेट नामक एक प्रकार के नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनाता है जिसे पूरी तरह से विघटित होने में लगभग 10 साल से अधिक का समय लग सकता है। वहीं तंबाकू उत्पादों के रैपर के कचरे तो कई दशकों तक जस के तस बने रहते हैं। ये समुद्री तटों पर एकत्रित होकर जलजीवों के लिए तो हानिकारक साबित हो ही रहे हैं साथ ही जो रैपर मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, वह उस भूमि की उपज को साल-दर-साल कम करते जाते हैं। तंबाकू की खेती और इसके दुष्प्रभावों के बारे में भी कई अध्ययनों में जिक्र मिलता है। भारत में तंबाकू उत्पादन के लिहाज से देखें तो आंध्र प्रदेश (45%), कर्नाटक (26%), गुजरात (14%), उत्तर प्रदेश (5%), तमिलनाडु (2%), बिहार (2%) और पश्चिम बंगाल (1%) इसके बड़े उत्पादक राय हैं। तंबाकू की खेती के बारे में जानने के लिए हमने आंध्र प्रदेश के एक उत्पादक से संपर्क किया (यहां नाम देना उचित नहीं है)। खैर, किसान बंधु बताते हैं, तम्बाकू बहुत मेहनत से उपजने वाले फसलों में से एक है, जिसकी देखरेख के लिए कई प्रकार के कीटनाशक और भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। सोचिए इससे जमीन और पर्यावरण को कितना नुकसान होता होगा?

भारत में सोलर एनर्जी को बढ़ाने पर जोर, स्वदेशी बनाने में आएगा इतना मोटा खर्च

नई दिल्ली. परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के घटते जाने और पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए भारत ही नहीं पूरे विश्व में जोर दिया जा रहा है. भारत में भी सोलर एनर्जी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें की जा रही हैं लेकिन सौर ऊर्जा विनिर्माण को स्वदेशी बनाने के लिए देश में मोटे निवेश की जरूरत पड़ेगी. सौर विनिर्माण की वैल्यू चेन को स्वदेशी बनाने के लिए अगले 3-4 वर्षों में 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (53,773 करोड़ रुपये) के पूंजीगत निवेश की जरूरत पड़ेगी. यह बात सीईईडब्ल्यू-सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस (सीईईडब्ल्यू-सीईएफ) के स्वतंत्र अध्ययन 'मेकिंग इंडिया ए लीडर इन सोलर मैन्युफैक्चरिंग' में सामने आई है. गुरुवार को जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने से घरेलू सोलर मॉड्यूल निर्माताओं को 2030 तक 30 बिलियन अमरीकी डॉलर (2.3 लाख करोड़ रुपये) (15 रुपये/ वाट पीक की दर से 150 गीगावाट बिजली की बिक्री से) राजस्व हासिल करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा, यह लगभग 41 हजार श्रमिकों के लिए नए रोजगार भी पैदा कर सकता है. काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) के प्रोग्राम लीड ऋषभ जैन ने कहा, '2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म-आधारित क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य पाने और दीर्घकालिक नेट-जीरो महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा एक आधारशिला की तरह है. वर्तमान में जारी भू-राजनीतिक और ऊर्जा संकट इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भरता घटाई जाए और ऊर्जा क्षेत्र में बदलावों के लिए प्रमुख उद्योगों के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद घरेलू सप्लाई चेन तैयार की जाए. वैश्विक स्तर पर कई देश अपनी सोलर सप्लाई चेन में विविधता लाने के लक्ष्य तय कर रहे हैं.'

पर्यावरण के लिये ज़्यादा कार्रवाई हो, वरना पृथ्वी के मानव बलिदान का क्षेत्र बन जाने का जोखिम

मुंबई। मानवाधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि वातावरण को एक प्रमुख मुद्दा बनाने के लिये, विश्व का पहला सम्मेलन, पाँच दशक पहले स्वीडन में हुआ था, तब से ये समझ बढ़ी है कि अगर इनसानों ने पृथ्वी की देखभाल करने में कोताही बरती, तो ये ग्रह मानव बलिदान का क्षेत्र बनकर रह जाएगा. पृथ्वी की रक्षा के लिये आगे की कार्रवाई पपर चर्चा करने के लिये, इस सप्ताह स्टॉकहोम में ताज़ा विचार-विमर्श शुरू होने वाला है, उस सन्दर्भ में सोमवार को, विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि ऐसे कहीं ज़्यादा विशाल प्रयासों की आवश्यकता है जिनके ज़रिये हर साल लाखों ज़िन्दगियाँ बचाई जा सकें.

संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मानवाधिकर विशेषज्ञ डेविड बॉयड ने इन पुकारों की अगुवाई की है कि देशों को सकारात्मक बदलाव लाने के लिये संवैधानिक बदलाव लागू करने होंगे और मज़बूत पर्यावरणीय क़ानून बनाने होंगे. उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के सभी विचार-विमर्श, इस समझ से निकलने चाहिये कि हर किसी को स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है. विषैले पदार्थों और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष रैपोर्टियर मार्कोस ऑरिलाना ने भी उन पुकारों को समर्थन देते हुए कहा है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिये कि मानवाधिकारों ने किस तरह, 1972 के मूल स्टॉकहोम घोषणा-पत्र के प्रमुख तत्वों के लिये प्रेरणा दी थी. उन्होंने कहा, ÷अन्तरराष्ट्रीय पर्यावरणीय क़ानून को अपना रास्ता बदलने और पर्यावरण संरक्षण के लिये, एक मानवाधिकार आधारित रास्ता अपनाने के लिये, ये एक महत्वपूर्ण लम्हा है.

अनेकानेक लाभ- इन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने ज़ोर दिया है कि मानवाधिकारों को पर्यावरणीय कार्रवाई के केन्द्र में रखने से, वायु गुणवत्ता, स्वच्छ जल, स्वास्थ मिट्टी और टिकाऊ तरीक़े से उत्पादित खाद्य पदार्थों के लिये सकारात्मक प्रभाव होंगे. उनका कहना है कि मानवाधिकार आधारित रवैया अपनाने से, हरित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और विषैले पदार्थों के उन्मूलन और आदिवासी लोगों के अधिकारों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी. इन विशेषज्ञों ने कहा है कि पर्यावरणीय कार्रवाई में प्रगति के रास्ते में व्यवधान खड़े करने से अनेक चुनौतियाँ सामने हैं जिनमें जलवायु झटके, जैव विविधता का नुक़सान और प्रदूषण - इन सबका असर मानवाधिकारों का आनन्द उठाने पर लड़ता है. जिनीवा स्थित यूएन मानवाधिकार परिषद ने, अक्टूबर 2021 में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव में, स्वछ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार को पहली बार मान्यता दी थी. ये प्रस्ताव, सिविल सोसायटी संगठनों, युवा समूहों, देशों के मानवाधिकार संस्थानों और आदिवासी जन के दशकों के प्रयासों का फल था. अनेक मानवाधिकार विशेषज्ञों ने देशों को प्रोत्साहित किया है कि वो यूएन महासभा को, स्वछ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार को उसी तरह मान्यता देने के लिये प्रोत्साहित करें जिस तरह यूएन मानवाधिकार परिषद ने मान्यता दी है.इन विशेष मानवाधिकार विशेषज्ञों ने एक वक्तव्य में कहा है, ÷स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार पर यूएन महासभा का प्रस्ताव पारित होने से अधिकारों पर कार्रवाइयों की तात्कालिकता मज़बूत होगी.÷

हम सभी इस अदभुत ग्रह पर बसने के लिये, असाधारण रूप से सौभाग्यशाली हैं, और हमें एक स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का प्रयोग, ये सुनिश्चित करने के लिये करना चाहिये कि सरकारें, व्यवसाय और लोग, मानवता के इस साझा घर का ख़याल रखने में बेहतर काम करें.÷विशेष रैपोर्टेयर और स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ, यूएन मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और वो किसी विशिष्ट मानवाधिकार थीम या देश की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करते हैं. वो किसी देश या सरकार से स्वतंत्र होते हैं; और उन्हें उनके काम के लिये, संयुक्त राष्ट्र से कोई वेतन नहीं मिलता है.

पर्यावरण बचाने को परसतराई के ग्रामीणों की पहल

बालोद। ग्राम परसतराई के युवा और बुजुर्गों ने मिलकर एक अनोखा पहल किया है और कहा भी जाता है कि जब युवा अपने युवा शक्ति के साथ और बुजुर्गों अपने जीवन के अनुभव के साथ मिलकर कोई कार्य करे तो असंभव से भी असंभव कार्य संभव हो जाता है इसी के तर्ज ग्रामीणों ने मिलकर विगत वर्षों से ईंट के ढेर पर उगे हुए 15 फीट के चारी पीपल के पेड़ को वहां से जड़ सहित हटाकर एक सुरक्षित स्थान तालाब के किनारे पर रोपित किया गया। युवाकांत सिन्हा स्वयंसेवक पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका एकमात्र कारण पेड़-पौधों की कटाई है। यदि समय रहते पेड़-पौधों का संरक्षण नहीं किया गया तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसका प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी पर पड़ेगा। पर्यावरण को बचाने का एकमात्र उपाय अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना व संरक्षित करना बेहद जरूरी है। जब भी अवसर मिले हमें एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। पौधारोपण करने के साथ-साथ उनका संरक्षण करना अनिवार्य है। बिना संरक्षण के अधिकांश पौधे लगाने के कुछ दिन बाद ही सूख जाते हैं। पौधों की पेड़ बनने तक देखभाल करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इससे के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए।

वृक्षारोपण करने में महत्वपूर्ण योगदान वरिष्ठ नागरिक हीरा लाल सिन्हा, उपसरपंच तीजू सिन्हा, रमेश, कौशल गजेंद्र ,युवाकांत सिन्हा यशराज गजेंद्र, ग्राम पंचायत परसतराई विशेष सहयोग रहा। एनटीसीएफ के तत्वावधान में शिक्षकों के नवाचार के प्रोत्साहन करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें पेडागाजी अर्थात खिलौने आधारित शिक्षण से बच्चों के गुणवत्ता स्तर को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। एनईपी 2020 में टायपेडगाजी को प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसी विषय पर जिला एवं अन्य जिलों से वर्चुअल जुड़े अतिथि शिक्षकों ने बधों के अभिव्यक्ति कौशल में खिलौने की भूमिका व महत्व पर चर्चा की। पाठ्यक्रम का अध्ययन अध्यापन में खिलौने आधारित शिक्षा को कैसे? किस रूप में देखते हैं और पढ़ाते वक्त खिलौने का क्या महत्व है? कैसे शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को हम खिलौने के माध्यम से बढ़ा सकते हैं? उनके इस तर्क में भाषाई कौशल ,वैज्ञानिक अवधारणा का विकास कर सकते हैं। मुख्य अतिथि अनुराग त्रिवेदी डीएमसी, विशिष्ट अतिथि जीएल खुरश्याम एपीसी, रागनी अवस्थी एपीसी रायपुर व अध्यक्षता अरुण साहू अध्यक्ष एनटीएफसी व कार्यक्रम प्रभारी कैशरीन बैग ने की। कार्यक्रम में चित्रमाला राठी, लोकेश्वरी कश्यप सिंगापुर, मोनू गुप्ताऋषि प्रधान आदि शामिल थे।

बढ़ रहा है वायुमंडलीय हीलियम का स्तर, वैज्ञानिकों ने लगाया पता- शोध

मुंबई। वातावरण में हीलियम का स्तर बढ़ रहा है इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व तकनीक का इस्तेमाल किया। एक ऐसे मुद्दे को हल करना है जो दशकों से वायुमंडलीय रसायनज्ञों के बीच बहस का मुद्दा बना हुआ है। इस बात का पता यूसी सैन डिएगो में स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी के वैज्ञानिकों ने लगाया है।

4-हीलियम (4एचई) समस्थानिक की मात्रा वायुमंडल में बहुत अधिक बढ़ रही है क्योंकि 4एच जीवाश्म ईंधन के जलने के दौरान निकलता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह बहुत कम लेकिन पहली बार स्पष्ट रूप से मापने योग्य दर से बढ़ रहा है। 4एच समस्थानिक से ग्रीनहाउस जैसा प्रभाव नहीं होता है जो ग्रह को गर्म करता है, लेकिन इसके उपाय जीवाश्म-ईंधन के उपयोग के अप्रत्यक्ष रूप में काम कर सकते हैं। मुख्य अध्ययनकर्ता बेनी बिरनर ने कहा हमारा प्रमुख काम वायुमंडलीय हीलियम की मात्रा के बारे में वैज्ञानिक समुदाय में एक लंबे समय से चल रहे विवाद को हल करना था। बिरनर यूसी सैन डिएगो में स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी में पोस्टडॉक्टरल शोधकर्ता हैं। आइसोटोप 4एचई पृथ्वी की परत में रेडियोधर्मी के नष्ट होने से निर्मित होता है और जीवाश्म ईंधन के समान जलाशयों में जमा होता है, विशेष रूप से प्राकृतिक गैस की तरह। जीवाश्म ईंधन के निकलने और जलने के दौरान, 4एचई निकलती है, जो औद्योगिक गतिविधि के मूल्यांकन करने के लिए एक उपकरण की तरह काम करता है। अध्ययन की सफलता उस तकनीक में है जिसका उपयोग स्क्रिप्स ओशनोग्राफी टीम ने यह मापने के लिए किया था कि वातावरण में कितना हीलियम है। बिरनर और स्क्रिप्स भू-वैज्ञानिक जेफ सेवरिंगहॉस, बिल पापलॉस्की और राल्फ कीलिंग ने 4 एचई समस्थानिक की तुलना सामान्य वायुमंडलीय गैस नाइट्रोजन के स्तर से करने के लिए एक सटीक विधि बनाई। क्योंकि वातावरण में नाइट्रोजन का स्तर स्थिर है, एचई / एन2 में वृद्धि वातावरण में 4 एचई बढ़ने की दर का संकेत है। सह-अध्ययनकर्ता और स्क्रिप्स ओशनोग्राफी जियोकेमिस्ट राल्फ कीलिंग, प्रसिद्ध कार्बन डाइऑक्साइड माप के पर्यवेक्षक, जिन्हें कीलिंग कर्व के रूप में जाना जाता है।

सदी के अंत तक 3.2 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान, अब तक के प्रयास नाकाफी

नई दिल्ली। तापमान 3.2 डिग्री बढ़ने की ओरपवन ऊर्जा की लागत पिछले दो दशक में 55 प्रतिशत कम हुई पवन ऊर्जा की लागत पिछले दो दशक में 55 प्रतिशत कम हुई पर्याप्त स्वच्छ विकल्प के बावजूद दुनिया में इन विकल्पों पर प्रयास नहीं हो रहा है और इस तरह वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है। यह बात 4 अप्रैल, 2022 को इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की छठवीं मूल्यांकन रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में कही गई है।

करीब 3,000 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2019 में मानवकृत कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन 59 गीगाटन था, जो साल 1990 के मुकाबले 54 प्रतिशत अधिक था। कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में ये इजाफा ऊर्जा के लिए और उद्योगों में जीवाश्म ईंधन जलाने और मीथेन के उत्सर्जन से आया (देखें, चिंताजनक संकेत)। उत्सर्जन किस क्षेत्र में कितना होता है, इसकी शिनाख्त भी समान रूप से नहीं की जाती, जो इस तरफ इशारा करता है कि कार्बन उत्सर्जन व्यापक स्तर पर सब जगह समान मात्रा में नहीं होता। साल 2019 में वैश्विक स्तर पर होने वाले कार्बन उत्सर्जन में कम विकसित देशों की भागीदारी सिर्फ 3.3 प्रतिशत थी। कम विकसित देशों में साल 1990 से 2019 के बीच प्रति व्यक्ति कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन 1.7 टन था, जबकि उसी उवधि में औसत वैश्विक उत्सर्जन 6.9 टन था। साल 2019 में दुनियाभर की आबादी का 41 प्रतिशत हिस्सा उन देशों में रहता था, जहां प्रति व्यक्ति कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन 3 टन से कम था। रिपोर्ट में इकलौता सकारात्मक पहलू यह है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सालाना

बढ़ोतरी पहले के मुकाबले कम हुई है। साल 2010-2019 के बीच ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सलाना 1.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि साल 2000-2009 के बीच ये बढ़ोतरी 2.1 प्रतिशत थी। दुनिया के 18 मुल्कों ने कार्बन रहित ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा की जरूरतें कम कर 10 सालों में लगातार ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन कम किया है। हालांकि, वैश्विक तापमान में इजाफे को औद्योगिकीकरण के पूर्व के स्तर पर लाने यानी 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिस स्तर पर ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाना है, उसके मुकाबले ये प्रयास नाकाफी हैं। अगर साल 2020 में लागू की गई मौजूदा नीति को मजबूत नहीं किया गया, तो साल 2100 तक वैश्विक तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा तय है। यहां तक कि पेरिस समझौते (जिसे नेशनली डिटर्मिंड कंट्रीब्यूशन भी कहा जाता है) पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने जो शपथ ली हैं, वे भी अपर्याप्त हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पेरिस समझौते के तहत अक्टूबर 2021 तक अपनाए गए उपायों को भी शामिल कर लिया जाए, तो वैश्विक तापमान में साल 2100 तक 2.8 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। इस विफलता में मौजूदा कोयला, तेल व गैस जैसे जीवाश्न ईंधन पर निर्भर ढांचे से होने वाले कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन की भूमिका है। तात्कालिक तौर पर सी1 एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आईपीसीसी ने इस संबंध में बताया है कि तापमान में इजाफे को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने के लिए क्या किया जा सकता है। हालांकि इसमें तात्कालिक रूप से तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इजाफा हो सकता है, लेकिन तकनीक की मदद से इसमें कमी लाई जा सकती है। इस तकनीक में वायुमंडल से कार्बन डाईऑक्साइड को सोख लिया जाता है। सी1 हासिल करने के लिए साल 2030 तक कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में 41 प्रतिशत तक कमी लानी होगी और उत्सर्जन को साल 2019 के स्तर पर यानी साल 2030 तक उत्सर्जन को 31 गीगाटन पर लाना होगा। सबसे जरूरी है कि साल 2050 तक साल 2019 की तुलना में कोयला, तेल और गैस के इस्तेमाल में क्रमशः 95 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 45 प्रतिशत तक की कमी लानी होगी। ऐसा संभव हो सकता है कि क्योंकि दुनिया में भारी मात्रा में किफायती समाधान मौजूद हैं और कुछ समाधानों के इस्तेमाल में तेजी भी आ रही है। साल 2010 के बाद से न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन तकनीकों की कीमत में कमी आई है। इकाई की कीमत के आधार पर सौर ऊर्जा तकनीक की कीमत में 85 प्रतिशत, पवन ऊर्जा तकनीक की कीमत में 55 प्रतिशत और लिथियम बैटरी की कीमत में 85 प्रतिशत तक की गिरावट आई है (देखें, हरित व किफायती)। साल 2010 के बाद से इसके इस्तेमाल में भी बढ़ोतरी हुई है। सौर ऊर्जा संचालित वाहनों के इस्तेमाल में 10 गुना और बिजली चालित वाहनों के इस्तेमाल में 100 गुना इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में इस इजाफे की वजह ÷शोध व विकास, पायलट प्रोजेक्ट व प्रदर्शनी के लिए फंडिंग और मांग में बढ़ोतरी के लिए सब्सिडी जैसे लुभावने प्रस्ताव÷ को बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्सर्जन कम करने के बहु-विकल्प जैसे सौर व पवन ऊर्जा, शहरी हरित बुनियादी ढांचा, वन व फसल/ग्रासलैंड, खाद्य कूड़ा प्रबंधन, खाद्य पदार्थों की कम बर्बादी तकनीकी रूप से व्यावहारिक और किफायती है तथा आम लोग इसे अपना भी रहे हैं। उत्सर्जन कम करने के कम खर्चीले उपायों से प्रति टन उससे कम कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन करने पर 100 अमेरिकी डॉलर खर्च होगा। इससे साल 2030 तक वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन आधा हो सकता है। बल्कि रिपोर्ट में तो यह तक कहा गया है कि इन उपायों पर जो खर्च होगा, उसके मुकाबले वैश्विक ऊष्णता कम करने में ज्यादा फायदा होगा। कार्बन को कम करने में निवेश करने से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जरूरतों को कम करने के उपाय मसलन पौधा-आधारित भोजन या पैदल चलना अथवा साइकिल का इस्तेमाल नई नीतियों को अपनाने के मुकाबले परिवहन, उद्योग, वाणिज्यिक व आवासीय सेक्टरों में वैश्विक स्तर पर साल 2050 तक ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में 40 से 70 प्रतिशत तक की कमी और लोगों की सेहत में सुधार ला सकता है।

मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन में दिए गए 50 लाख एक हजार 772 नल कनेक्शन

भोपाल मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन में विभिन्न कार्यों के संचालन की जानकारी निवास में समीक्षा बैठक में प्राप्त की। इस दौरान बताया गया कि मिशन में प्रदेश में पचास लाख से अधिक नल कनेक्शन हो गए हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 50 लाख एक हजार 772 हो गई है। प्रदेश में दो वर्ष पहले मिशन में प्रगति 17 लाख 50 हजार नल कनेक्शन थी, जो सिर्फ दो वर्ष की अवधि में बढ़ते हुए 50 लाख से ज्यादा हो गई है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रसन्नता व्यक्त की और जल जीवन मिशन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को बधाई दी। प्रदेश में गत 2 वर्ष में प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुसार जल जीवन मिशन के कार्यों को निरंतर क्रियान्वित किया गया है। मध्यप्रदेश अनेक राज्यों से इस क्षेत्र में आगे है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में मध्यप्रदेश सक्रिय है। मध्यप्रदेश आगे भी गतिशील रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि घर-घर पीने का पानी पहुँचाने के लिए मिशन के प्रयास निरंतर चलेंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008